VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 05 SEP 2023 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2086)

Name of Candidate	Ishwar lal Gunjah.		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1295818.
Center	MN.	Date	5/09/2023

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है?

Do you agree with the view that there is a need to enact a new law for ensuring judicial accountability in India? (Answer in 150 words) 10

'न्यायपालिका' सरकार के प्रमुख तीन अंगों में शामिल है अतः न्यायिक जवाबदेही द्वारा न्यायपालिका को संविधान व जन के प्रति जवाबदेही बनाया जाना चाहिए।

जैसे- CJI ऑफिस को RTI के दायरे में लाने का कदम

न्यायिक जवाबदेही के लिए नए कानून की प्रासंगिकता

1.7 बढ़ता न्यायिक अतिक्रमण जैसे- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'NJAC' (99th CAA) को रद्द करना विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप का उदाहरण है।

2.7 न्यायपालिका द्वारा अनु० 142 (पूर्ण न्याय) का बढ़ता मनमाना प्रयोग।

उदा० - सर्वोच्च न्यायालय ने NH के 500मीटर क्षेत्र में शराबबंदी का आदेश देना जो व्यवहार्य नहीं है।

3.7 न्यायपालिका में अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली एवं बढ़ता भाई-भतीजेवाद को रोकने के लिए नया कानून आवश्यक है।

4.7 आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना
जैसे- लंबित मामलों की सुनवाई में देरी
4 करोड़ लंबित मामलें

5.7 न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त, अधिक पारदर्शी व जवाबदेही बनाने हेतु।

हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालतों की live streaming, ई- कोर्ट परियोजना, FASTER व SUVAS जैसे कदमों से न्यायिक जवाबदेही की तरफ कदम बढ़ाया गया है।

अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अधिक जवाबदेह न्यायप्रणाली की तरफ बढ़ा जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) में संवैधानिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य रहा है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए।

Constitutionally reconciling Fundamental Rights with the Directive Principles of State Policy (DPSPs) has been a tough task since the inception of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान के भाग -3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक मौलिक अधिकार व भाग-4 में अनुच्छेद -37 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल है।

मौलिक अधिकार व DPSP में टकराव के कारण

↳ अनुच्छेद -13 में संसद को मौलिक अधिकारों में कटौती से रोका गया है। जबकि अनुच्छेद - 368 संविधान संशोधन की शक्ति देता है। अतः दोनों की व्याख्या को लेकर टकराव हुआ

उदा०- शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद
1965 में सर्वोच्च न्यायालय ने (FR) में संशोधन को संसद की शक्ति माना।

2.7 संपत्ति के मौलिक अधिकार अनु. 19(1)(f) व अनु. 31 और DPSP अनु. 39 के टकराव के कारण जैसे- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद -1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया।

3.7 DPSP को लागू करने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना जैसे भूमि सुधार, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण।

उदा- चम्पकम दुराई राजन वाद

केशवानंद भारती वाद -1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढाँचे का सिद्धान्त दे कर दोनों को सम्मान महत्व दिया।

मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में अदालत ने DPSP और मौलिक अधिकारों को एकदूसरे का पूरक माना और दोनों में सामंजस्य को संविधान का बुनियादी ढाँचा माना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्यों और भारत में नीति-निर्माण को आकार देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Discuss the functions performed by the Prime Minister's Office (PMO) and its role in shaping policy-making in India. (Answer in 150 words) 10

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का गठन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नियंत्रण में बिजनेस एडवाइजरी रूल्स के तहत किया गया जो 'प्रधानमंत्री' को प्रशासनिक व सचिवीय सहायता प्रदान करता है।

नीति निर्माण में PMO की भूमिका

1) सुधारों का व्यापक एजेंडा तैयार करने में प्रधानमंत्री की सहायता करता है।
उदा० - आत्मनिर्भर भारत अभियान

2) कैबिनेट व प्रधानमंत्री के मध्य नीति-निर्माण संबंधी इनपुट को ग्रहण करता है।
उदा० - प्रधानमंत्री के प्रस्ताव, सुधार विचारों को सामने लाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. PMO परमाणु ऊर्जा, बाह्य सुरक्षा व राष्ट्रीय मुद्दों पर विभिन्न एजेंसियों से सीधा संपर्क रखता है।

उदा० परमाणु ऊर्जा आयोग PMO के तहत काम करता है।

4. अन्य कार्य → प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का प्रबंधन
→ प्रधानमंत्री की यात्रा में डेटा व पॉलिसी इनपुट

अतः PMO की भूमिका शासन में बहुआयामी है यह PM के लिए थिंक टैंक व पॉलिसी इन्स्टिट्यूट की भूमिका निभाता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने और उन पर पुनर्विचार करने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

Re-examination and reconsideration of the provisions of Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) requires striking a balance between concerns of civil liberties and human rights, and maintaining and protecting the sovereignty and integrity of India. Comment. (Answer in 150 words) 10

IPC की धारा - 124(A) राजद्रोह से संबंधित है। हिंसा द्वारा चुनी हुई सरकार, शासन व्यवस्था का उखाड़ना, अस्थिर करने वाले कार्यों को राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है।

राजद्रोह
- एक संज्ञेय अपराध है।
- एक गैर-जमानती अपराध है।
- आजीवन कारावास की सजा।
- दोषी या अपराधी को सरकारी नौकरी, पासपोर्ट धारण करने से रोकता है।

नकारात्मक पक्ष

* NCRB के अनुसार 2015 से 2020 के मध्य 356 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए लेकिन (3.3%) ही दोषसिद्ध।
* इसका व्यापक दुरुपयोग होता है।

* एक औपनिवेशिक कानून है। ब्रिटेन ने 2009 में राजद्रोह को समाप्त किया अतः भारत में अनावश्यक है।

* ICCPR कन्वेंशन के तहत इसे समाप्त करना। 113 देशों ने राजद्रोह को समाप्त कर दिया है।

* मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन होता है

पक्ष में तर्क → केदारनाथ सिंह बनाम बिहार 1962

मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी वैधता को बनाए रखते हुए असाधारण स्थिति में प्रयोग करने की बात कही है।

* आतंकवाद, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता के लिए जरूरी है।

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य

वाद - 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक निर्देश दिए अतः उनका पालन करते हुए इस पर वैधानिक चर्चा होनी चाहिए।

5. "ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।" टिप्पणी कीजिए।

"Citizen participation is key to the success of e-governance initiatives in rural India." Comment. (Answer in 150 words) 10

ई-गवर्नेंस पहलों द्वारा शासन प्रक्रिया में 'ICT' व प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही, प्रतिक्रियाशील व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने से है। जैसे → ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रणाली

ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी की आवश्यकता —

1. डिजिटल डिवाइड के कारण मात्र 31% ग्रामीण आबादी की पहुँच ही इंटरनेट तक है अतः NGO, SHG, व सिविल सोसाइटी द्वारा ई-गवर्नेंस का सामूहिक प्रयोग को बढ़ावा देना। जैसे - राजस्थान सरकार के ई-मित्र केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदान करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2.> डिजिटल साक्षरता के अभाव में ग्रामीण आबादी DBT, डिजिटल लेन-देन सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते है।

3.> मनरेगा, PDS, पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु नागरिक भागीदारी आवश्यक है।

नागरिक भागीदारी के प्रयास

- * डिजिटल साक्षरता मिशन
- * कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- उमंग APP
- * डिजी लॉकर दस्तावेजों का डिजिटलीकरण
- my Govt.in द्वारा फीडबैक
- * राजस्थान सरकार की जन सूचना पोर्टल

अतः ई-गवर्नेंस में नागरिकों की भागीदारी द्वारा सेवा वितरण को प्रभावी बनाकर जनमित्र-शासन व सुशासन के लक्ष्यों को पाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. आपके अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपनी शुरूआत के बाद से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल रहा है?

How far do you think the Aspirational District Programme has been able to achieve its objectives since its inception? (Answer in 150 words) 10

'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के तहत देश के सर्वाधिक पिछड़े 112 जिलों का सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर समग्र विकास करना।

घटक
- Convergence (व्यापकता को बढ़ाना)
- Compition (प्रतिस्पर्धा बढ़ाना)
- Collabration (सहयोग बढ़ाना)

उद्देश्य
- पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार
- 'चैंपियन ऑफ चेंज' के रूप में जिलों का विकास करना
- रैंकिंग द्वारा 'रियल टाइम' प्रोग्रेस का आकलन करना।
- सापेक्षिक वंचना को कम करना जैसे- नक्सल क्षेत्र के 60 से अधिक जिलों का शामिल होना

* P&H पोषण व स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार
* नीति आयोग द्वारा बॉटम-अप दृष्टिकोण के कारण; जिलों में स्थानीय आधार पर समाधान
* लिंगानुपात में सुधार हुआ — NFHS-5 के अनुसार
* जिलों से जितस्पर्धा बढ़ी
* प्रशासन की उपस्थिति में वृद्धि हुई।

सफलता

हालाँकि वित्तीय आवंटन व केन्द्र-राज्यों के विवाद के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हुई लेकिन व्यापक स्तर पर यह सफल रहा।

अतः 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' की सफलता के बाद केन्द्रीय बजट 2022-23 में 500 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. NGO क्षेत्रक को आगे बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

Technology has a crucial role to play in advancing the NGO sector and improving outcomes for beneficiaries. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

भारत में 33 लाख से अधिक NGO है लेकिन 'NGO दर्पण' पोर्टल पर मात्र 5% NGO ही पंजीकृत है जो NGO क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता को बताता है।

NGO क्षेत्रक को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी भूमिका

1.) NGO वेबसाइट व App द्वारा कॉर्पोरेट व दान दाताओं को जोड़ सकता है।
eg- प्रथम NGO का पोर्टल

2.) लाभार्थियों तक पहुँच को बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया, youtube का प्रयोग कर सकता है।
Eg- स्माइल फांउडेशन द्वारा यूट्यूब से प्रचार-प्रसार करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3.) ब्लॉकचेन, Big data, क्लाउड कम्प्यूटिंग द्वारा NGO पॉलिसी मेकिंग में एक इनपुट का काम कर सकता है।

4.) साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल जागरूकता जैसे कार्यों में NGO का विस्तार संभव

लाभार्थियों के आउटकम को बेहतर करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका —

* खाद्य सामग्री, कपड़े, दवाओं के दान द्वारा बेघर, गरीबों की सहायता संभव है।
eg- गूंज NGO द्वारा सामग्री का वितरण
* पहुँच को व्यापक किया जा सकता है।
* डिजिटल पॉर्टल, ऑनलाइन मेंबरशिप, ऑनलाइन कैंपेनिंग द्वारा बेहतर सेवावितरण

अतः प्रौद्योगिकी NGO की प्रभावशीलता को बढ़ाकर बेहतर नागरिक समाज का निर्माण संभव है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. तकनीकी और उन्नतर शिक्षा के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश से जुड़े निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

Discuss the implications associated with the entry of foreign educational institutions for technical and higher education in India. (Answer in 150 words) 10

नई शिक्षा नीति -2020 ने FHEI, को भारत में शिक्षण की अनुमति देने की बात कही।

'UGC' ने दिशा-निर्देश जारी कर TOP-500 रैंक वाले FHEI को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी

सकारात्मक → नई तकनीक व शिक्षण प्रणाली

- वेल्थ ड्रेन व ब्रेन ड्रेन में कमी होगी
- शिक्षा आधारसंरचना का विकास
- ज्ञान आधारित महाशक्ति बनना
- R&D में बढ़ोतरी
- वर्ल्ड क्लास पाठ्यक्रम

नकारात्मक → फीस तय करने की स्वतंत्रता अतः गरीब बच्चे वंचित (असमानता)

→ भारतीय शिक्षा संस्थान कमजोर

→ व्यापक स्वतंत्रता का दुरुपयोग eg- डोनेशन फैलाना

अतः इसे शुरुआत में निगरानी के तहत ही लागू किया जाए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच फलता-फूलता संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। परीक्षण कीजिए।

The flourishing relationship between India and countries of Latin America has become a critical element of India's foreign policy. Examine. (Answer in 150 words) 10

लैटिन अमेरिका और भारत
का द्विपक्षीय व्यापार 150 बिलियन डॉलर
है। हाल ही में विदेश मंत्री ने लैटिन
अमेरिका के कई देशों की यात्रा की

महत्व → लिथियम का 35% आपूर्ति
अर्जेंटीना, बोलिविया व चिली
→ 40% तांबा लैटिन से आता है
→ 15% ऊर्जा आपूर्ति
g- वेनेजुएला, क्यूबा
- भारत का 16 बिलि. डॉलर का
निवेश है g फार्मा, ऑटो और
- IT पेशेवरों की मांग

चुनौती - भाषा की बाधा
e.g. स्पेनिश आदि
- चीन की बढ़ती रुचि
-> भौगोलिक दूरी

भारत ने लैटिन अमेरिका के कई देशों में नए दूतावास खोले हैं अतः संबंधों को बढ़ाकर भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को तय करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. ऋण-जाल कूटनीति क्या है? चीन की ऋण-जाल कूटनीति भारत के पड़ोस में भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करती है?

What is debt-trap diplomacy? How does China's debt-trap diplomacy impact India's interests in its neighbourhood? (Answer in 150 words) 10

चीन द्वारा BRI परियोजना के तहत सस्ता ऋण छुपी हुई शर्तों पर प्रदान किया जाता है। इसे ऋण-जाल नीति कहा जाता है

g- श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह 99 साल पर चीन पर लीज

भारत के हितों पर प्रभाव

→ दक्षिण एशिया के अधिकांश देश BRI के भागीदार बने है

g- Pak का CPEC प्रोजेक्ट

→ श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश में भारत के हितों पर नकारात्मक प्रभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- भारत की सुरक्षा को खतरा
  eg- ग्वादर बंदरगाह पर चीन
- चीन की मोतियों की माला द्वारा भारत को हिन्द महा. मे घेरा जा रहा है

भारत के कदम
- सागर मिशन पहल
- पडोसी पहले दृष्टिकोण
- बिम्सटेक के तहत सक्रियण
- भारत की सॉफ्ट लोन पॉलिसी
- आर्थिक कूटनीति का प्रयोग
  eg- LOC प्रदान करना
  श्रीलंका

भारत ऋण-जाल कुनीति से बचाने के लिए सॉफ्ट पॉवर का प्रयोग कर रहा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. विश्व भर के विभिन्न संविधानों का मिश्रण होने के बावजूद, भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता को आत्मसात किए हुए है। टिप्पणी कीजिए।

Despite being an amalgamation of various constitutions from across the world, the Indian Constitution imbibes social justice, pluralism, and equality through its various provisions. Comment. (Answer in 250 words) 15

'भारतीय संविधान' के संवैधानिक सलाहकार 'बी. एन. राव' व 'प्रारूप समिति' ने 160 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन कर भारतीय संविधान का निर्माण किया अतः कुछ आलोचक इसे उधार का थैला कहते है।

भारतीय संविधान में अन्य देशों से प्रावधान

↳ संविधान का 2/3 हिस्सा 'भारतीय शासन अधिनियम -1935' से लिया गया है।

2.7

USA से
- * प्रस्तावना का प्रारूप
- विधि की सम्यक प्रक्रिया
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- राष्ट्रपति पर महाभियोग
- * मौलिक अधिकार
- * उपराष्ट्रपति का पद

आयरलैंड
- * राज्यसभा में मनोनीत सदस्य
- * नीति निर्देशक तत्व

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3.7

ब्रिटेन:
- * संसदीय प्रणाली
- विधि का शासन
- * इकहरी नागरिकता
- * मंत्रीमंडल
- * एकल न्याय प्रणाली

कनाडा:
- * राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना
- अर्द्ध-संघीय प्रणाली

4. अन्य प्रावधानों में आपातकालीन उपबंध - जर्मनी से संविधान संशोधन - दक्षिण अफ्रीका से और समवर्ती सूची - आस्ट्रेलिया से ली गई है।

भारतीय संविधान में इन उपबंधों को भारतीयकरण करके ही स्वीकारा गया है—

1.7 सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में

↳ सामाजिक न्याय सोवियत संघ से लिया गया लेकिन भारत ने इसे विविधता व राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार स्वीकारा

जैसे- समानता व भिन्नता में सामंजस्य
- संपत्ति का अधिकार व आर्थिक समानता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- आरक्षण की सकारात्मक कार्यवाही भारतीय है जो जाति आधारित है।
- अर्थव्यवस्था का मिश्रित मॉडल DPSP के अनु. 38 में व अनु. 39 में

2) बहुलवाद और समानता के सन्दर्भ में

↳ भारत में 'पंथनिरपेक्षता' को स्वीकारा यह पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से अलग - सर्वधर्म सम्भाव आधारित है।

↳ विविधता का संरक्षण / धार्मिक, भाषायी, नस्लीय विविधता का संरक्षण

3) समानता का अधिकार अनु. 14-18 व धार्मिक स्वतंत्रता अनु. 25 - 28 तक जान

अतः डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों की अच्छी बातों को भारतीय सन्दर्भ में ही स्वीकारता है

12. हाल के कुछ घटनाक्रमों ने भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे को प्रकाश में लाया है। देश में वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के लिए कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Recent developments have brought to light the issue of criminalizing marital rape in India. Analyse the implications of ensuring legal protection for victims of marital rape in the country. (Answer in 250 words) 15

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा-375 के तहत विवाह व्यवस्था में होने वाला लैंगिक यौन उत्पीड़न अपराध नहीं माना गया है। वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने को लेकर हाल में चर्चा तेज हुई।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने : पक्ष में तर्क

1.> NFHS-5 के अनुसार 18-49 वर्ष की एक-तिहाई महिलाएं यौन हिंसा का शिकार वैवाहिक व्यवस्था में है।

2.> No मीन्स NO - नारीवादी संगठन विवाह व्यवस्था को पितृसत्तात्मक संगठन मानते है जो महिलाओं को मौलिक अधिकारों से वंचित करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3> संविधान के अनुच्छेद -14,15 के अनुसार समानता के अधिकार का उल्लंघन करते है
eg- आपराधिक कानूनों का लैंगिक भेदभावपूर्ण होना।

4> अमेरिका, यूरोपीय देशों सहित अधिकांश देशों ने इसे अपराध घोषित किया
eg- पाकिस्तान में भी आपराधिक है

विपक्ष में तर्क

* केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज हलफनामें में इसका विरोध किया।

* दुरुपयोग की व्यापक संभावना -
eg- दहेज रोकथाम अधि. 1961 का व्यापक दुरुपयोग

* साबित करना बेहद मुश्किल है। यह अदालतों में विवादों में बढोतरी करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* परिवार-व्यवस्था व विवाह-प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

* भारतीय समाज अभी अभिकृती के स्तर पर तैयार नहीं

यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस पर व्यापक विधिक चर्चा द्वारा एक अलग कानून बनाया जाए। वर्मा कमेटी ने भी इसे आपराधिक बनाने की सिफारिश की है। वैवाहिक बलात्कार पीड़िता के संरक्षण हेतु वन स्टॉप सेन्टर, मिशन शक्ति राष्ट्रीय पुर्नवास कोष, निर्भया फंड, FTCs की प्रणाली को सुधारू करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. "संघवाद के भारतीय मॉडल की अत्यधिक केंद्रीकृत होने के कारण आलोचना की जाती है, लेकिन यह राज्यों को पर्याप्त अवसर और स्वायत्तता भी प्रदान करता है।" विश्लेषण कीजिए।

"The Indian model of federalism has been criticized for being too centralized, but it also provides adequate space and autonomy to the states." Analyse. (Answer in 250 words) 15

भारत एक अर्ह- परिसंघीय मॉडल वाला देश है। सर्वोच्च न्यायलय के अनुसार भारत एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघवाद है। और 'संघवाद' संविधान का बुनियादी ढाँचा है।

eg- एस० आर० बोम्मई वाद -1992 में संघवाद को संविधान का मूल ढाँचा माना।

संघवाद में एकात्मक तत्व : भारतीय मॉडल

1. राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होना
2. राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र द्वारा
3. संघसूची में अधिक विषयों का शामिल होना तथा अनु० 248 अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र सरकार के पास होना
4. अनुच्छेद -356 द्वारा राज्यों में आपातकाल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5.7 'अखिल भारतीय सेवाओं' का होना।

6.7 'इकहरी नागरिकता' का प्रावधान

7.7 राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान अनु. 352, 360

8.7 केन्द्र द्वारा राज्यों में केन्द्रीय बलों की तैनाती का अधिकार

संघवाद का एकात्मकता की ओर झुकाव के कारण

* राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडता के लिए एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता
* भारत की विविधता व एकता में सामंजस्य
* औपनिवेशिक विरासत एवं ब्रिटेन का मॉडल
* समानता, अल्पसंख्यकों का संरक्षण

राज्यों को पर्याप्त अवसर व स्वायत्तता के प्रावधान भी शामिल है।

A7 सातवी अनुसूची में राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता एवं समवर्ती सूची पर पूर्ण समान अधिकार/शक्ति।

B) राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व

C) आर्थिक स्वतंत्रता / By- कराधान का अधिकार

D) वित्त आयोग द्वारा राजस्व में राज्यों की भागीदारी by 15th FC द्वारा 41%

E) G.S.T. परीषद में राज्यों की भूमिका

F) अंतराज्यीय परिषद व अनु॰ 131 के तहत केन्द्र पर वाद का अधिकार

H) कृषि, भूमि, जल, पुलिस जैसे राज्यसूची के मामलें प्रदान किए।

वर्तमान में केन्द्र सरकार, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, नीति-आयोग, स्थानीय-स्वशासन को वित्त व शक्तियों का हस्तांतरण, पैराडिप्लोमेसी को बढ़ावा दे रही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में नियुक्तियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय ने नियुक्ति प्रक्रिया को मूल रूप से बदल दिया है और इसके संभावित दूरगामी निहितार्थ भी हो सकते हैं। विवेचना कीजिए।

The recent judgment of the Supreme Court on appointments to the Election Commission of India (ECI) has fundamentally changed the appointment process and can have potentially far-reaching implications. Discuss. (Answer in 250 words) 15

सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद - 2023 में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली को बदल दिया।

उच्चतम न्यायालय का फैसला => 1) राष्ट्रपति एक सीमित समिति की सिफारिश से 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' व अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करेगा। यह समिति प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश (CJI) व लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से बनेगी। यह व्यवस्था जब तक संसद अन्य कानून नहीं बना देती तब तक लागू रहेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्णय के संभावित दूरगामी निहितार्थ

सकारात्मक → निर्वाचन आयोग (ECI) पर राजनीतिक प्रभाव कम होगा। जिससे वह अपने संवैधानिक दायित्व का प्रभावी निष्पादन कर पायेगा।
जैसे- निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव करवाना

→ मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के प्रति विपक्षी राजनीतिक दलों का विश्वास बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी

→ अन्य चुनाव सुधारों की राह खुलेगी जैसे- MCC को कानूनी बनाना, निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता निश्चित करना, कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना।

नकारात्मक
* न्यायिक अतिक्रमण को बढ़ावा देगा।
* कार्यपालिका व न्यायपालिका में टकराव बढ़ेगा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

* चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी होगी।

* अनुच्छेद - 324 के तहत निर्वाचनमण्डल की शक्तियां में कमी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय का यह

निर्णय सराहनीय पहल है। ~~सरकार को~~ दिनेश गोस्वामी, इन्द्रजीत गुप्ता व तारकुंडे कमेटी की चुनाव सुधार संबंधी सिफारिशों को लागू करते हुए। व्यापक चुनाव सुधार संबंधी अलग कानून बनाकर निर्वाचन आयोग को सशक्त करना चाहिए।

15. वैश्विक बदलावों के साथ समेकन और अर्थव्यवस्था के खुलने के परिणामस्वरूप लोक सेवाओं के लिए विविध चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण कुशल सेवा वितरण के लिए उनमें समग्र सुधारों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

Integration with the global trends and opening up of the economy has resulted in diversified challenges for the civil services, which require holistic reforms for efficient service delivery. Discuss. (Answer in 250 words) 15

LPG सुधारों और राज्य के व्यापक होते स्वरूप के साथ ही लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार, अकुशलता में बेहतरी हुई है। eg- भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक -86 है। (ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल)

लोक सेवाओं के लिए बदलती चुनौतियाँ

* बढ़ती सब्सिडी लोककल्याण ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया
* राजनीति में अपराधीकरण क्रोनी कैपिटलिज्म का बढ़ना
-> जटिल नीति निर्माण
* तीव्र तकनीकी बदलाव से प्रशासन में विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया eg- ब्लॉकचेन व NFT पर नीति-निर्माण
* जलवायु परिवर्तन - आपदा में बढ़ोतरी से संसाधनों पर दबाव eg- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
* बढ़ती जन आकांक्षाएँ eg सिविल सोसायटी दबाव समूहों का उदय

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कुशल सेवा वितरण के लिए सुधार की आवश्यकता

1-> ई- गवर्नेंस के संचालन हेतु लोक-सेवकों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी कौशल प्रदान करना -

eg- PPT बनाना, प्रोजेक्टर द्वारा VC

2-> नागरिकों को शासन में शामिल करने के लिए सुधार आवश्यक है-

eg- सिटीजन फीडबैक, नागरिक-चार्टर,

3-> लेट्रल इन्ट्री द्वारा विशेषज्ञता, कौशल, प्रबंधन व तकनीक का समावेश करना

4-> सुशासन, स्मार्ट गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सीमम गवर्नेंस द्वारा [3Es] को बढ़ाना

Efficativeness, Efficiency, Economy

5-> ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म को बढ़ावा देना होगा

मिशन कर्मयोगी द्वारा लोक-सेवकों को तकनीकी संबंधी, नवाचारी बनाना

↑

उठाए गए कदम

- * लोक सेवा गारंटी
- * जवाबदेही प्रणाली
- रूल बुक नौकरशाही की जगह रोल बेस्ड नौकरशाही
- * RTI, सिटिजन चार्टर, सामाजिक ऑडिट को बढ़ावा देना
- * ई-गवर्नेंस परियोजना द्वारा
  - CSC स्थापित करना
  - ई-कोर्ट
  - ई-डिस्ट्रिक्ट

जलवायु परिवर्तन, बढ़ता डिजीकरण, उभरती प्रौद्योगिकी का सामना करने के लिए लोक सेवाओं को अधिक जन सहभागी, कुशल बनाते हुए लोक सेवकों को बदलाव का एजेंट बनाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. भारत में ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में ओपन डेटा क्या भूमिका निभा सकता है? देश में ओपन डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में कौन-सी चुनौतियां विद्यमान हैं?

What role can open data play in promoting transparency and accountability in e-governance in India? What are the challenges in ensuring the quality and reliability of open data in the country? (Answer in 250 words) 15

'ई-गवर्नेंस' में ओपन डेटा 'इनपुट' की तरह कार्य करता है। यह नीति-निर्माण, नीति-क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

ई-गवर्नेंस में ओपन डेटा की भूमिका

- * योजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलना में
  eg- उर्वरक सब्सिडी
- * ओपन-डेटा द्वारा शासन में जन फीडबैक को शामिल
  eg- सेवा पर फीडबैक सर्वेक्षण, वोटिंग
- * कुशलता, मितव्ययता व दक्षता को बढ़ावा देना
- विकास कार्यों में तेजी
- क्षमता निर्माण करना
- * नागरिकों का सशक्तिकरण सूचना द्वारा
  eg- mygov.in
- * लक्षित नीति निर्माण
  eg- आयकर की स्लैब बनाते समय ई-कॉमर्स डेटा से क्रय शक्ति का विश्लेषण

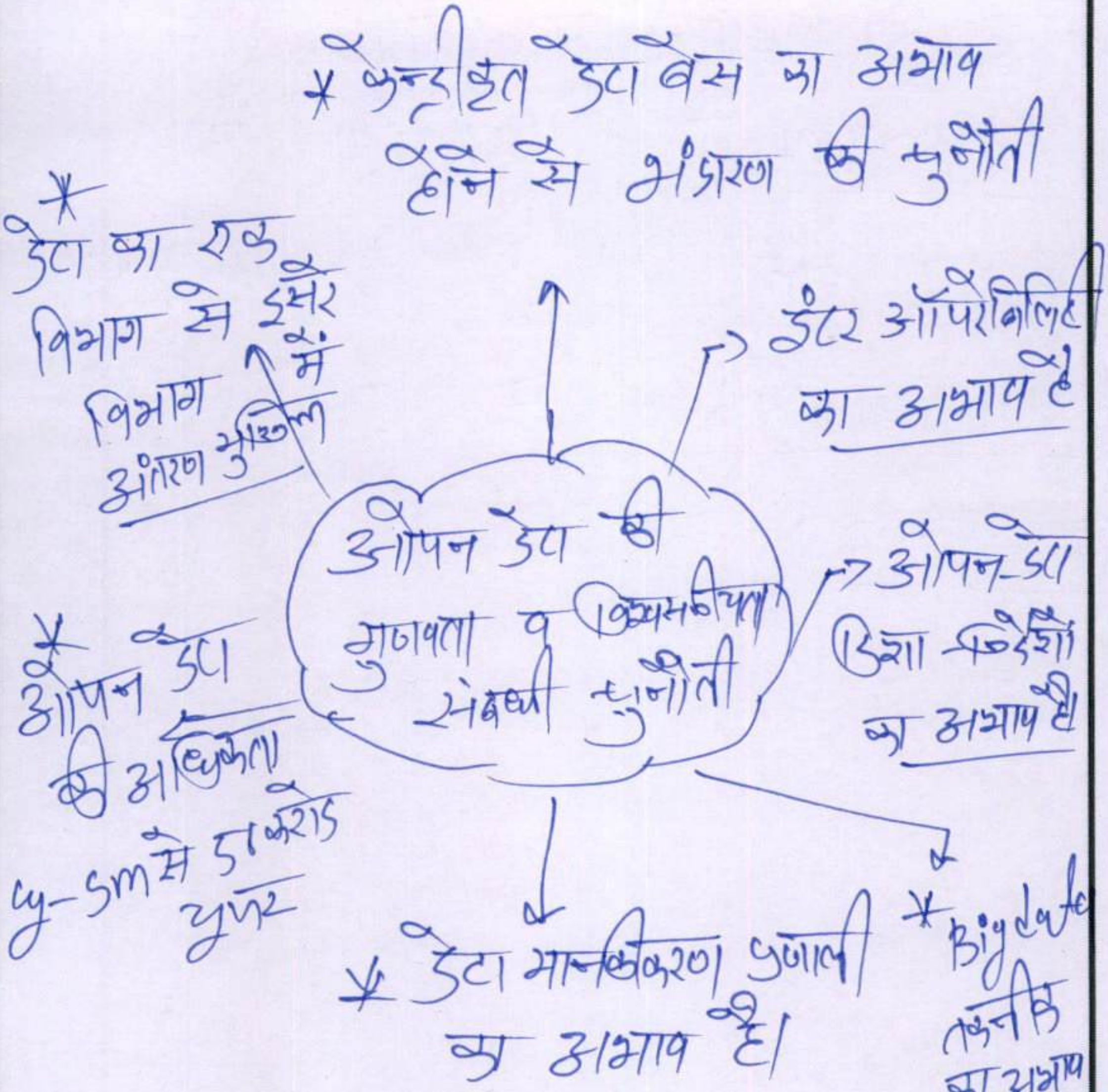

'ओपन डेटा' का प्रयोग करने के लिए विकेन्द्रीकृत डेटा बेस स्थापित करने, एज कम्प्यूटिंग को बढ़ावा देने, ~~[illegible]~~ थर्डपार्टी बिग डेटा पक्ष का उपयोग करना, ब्लॉकचेन, स्थानीय डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः ओपन डेटा द्वारा प्रशासन में प्रभावशीलता व पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है। डेटा के प्रसंस्करण, भंडारण व वर्गीकरण के लिए डेटा कानून भी जरूरी है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. भारत में 'जीरो फूड' बच्चों की व्यापकता को कम करने के लिए मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

To reduce the prevalence of 'zero food' children in India, maternal nutrition needs to be made a priority. Comment. (Answer in 250 words) 15

'पोषित माँ' अभियान के तहत मातृ पोषण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। मातृ पोषण द्वारा जीरो फूड बच्चों की व्यापकता को कम किया जा सकता है।

मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

1. NFHS-5 के अनुसार भारत में 67% बच्चें (5 वर्ष से छोटे) एनीमिया व 36% बच्चें स्टंटिंग का शिकार है।

2. भारत में हर-दूसरी महिला एनीमिया का शिकार है। जिससे गर्भवती माँ व शिशु दोनों के लिए ही खतरा बढ़ जाता है। मातृ मृत्यु दर – 90. शिशु मृत्यु दर – 35.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3-> प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पोषण की गुणवत्ता व उपलब्धता जरूरी है।

4-> जंक फूड वस्तुओं में मोटापन, डायबिटीज जैसे स्थायी विकार उत्पन्न होते है।

5-> खानपान को लेकर जागरूकता का अभाव है।

प्रयास/पहल ->
- पोषण 2.0 अभियान
- फूड फोर्टिफिकेशन द्वारा पोषण
  - eg- फोर्टिफाइड राइस
- सुपोषित माँ अभियान
- जननी शिशु सुरक्षा योजना
- मिशन शक्ति
- आँगनबाड़ी के तहत ICDS
- टीकाकरण हेतु मिशन इन्द्रधनुष

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना व PDS द्वारा पोषण सुरक्षा के प्रयास जारी है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

SDG-1 (No Poverty), SDG-2 (जीरो भुखमरी) SDG-3 (गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य) की पूर्ति करने में मातृ पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही जागरूकता, प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण को भी बढ़ावा देना होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. हाल ही में, केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी खाद्य सामग्रियों और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। भारत में लोक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंताएं क्या हैं? इनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है?

Recently, the Central government exempted all foods and drugs for rare diseases imported by people for personal use from customs duty. What are the concerns related to rare diseases as a public health issue in India? How can these be resolved? (Answer in 250 words) 15

दुर्लभ रोगों में ऐसे आनुवांशिक या गैर-संक्रामक रोगों को शामिल किया जाता है जो सामान्यतः अप्रत्याशित होते हैं. eg- सिकल सेल एनीमिया, तांत्रिका तंत्र विकलांगता आदि।

दुर्लभ रोगों संबंधित चिंताएं

1-> जागरूकता के अभाव में इन्हें दैवीय प्रकोप माना जाता है।

2-> समयबद्ध इलाज संभव नहीं।

3-> महंगा इलाज होने के कारण अधिकांश की पहुंच से बाहर है
eg- 45 लाख का एक इंजेक्शन तंत्रिका विकलांगता हेतु।

4-7 चिकित्सकों व दुर्लभ रोग संबंधी सेवाओं का अभाव होना
Eg- जाँच, निवारण का अभाव

5-7 लोक स्वास्थ्य प्रणाली की खस्ता हालत के कारण out of पॉकेट खर्च 65%

6-7 स्वास्थ्य पर मात्र 1.5% GDP का ही व्यय है।

समाधान के उपाय

* दुर्लभ रोगों पर एक राष्ट्रीय ब्लू प्रिंट का निर्माण
* अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली को एकीकृत
* जागरूकता के लिए व्यापक कैंपेन
* R&D को बढ़ावा देना
* निजी क्षेत्र को आकर्षित करना
* सरकार द्वारा इलाज पर आर्थिक सहायता
* राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन में दुर्लभ रोगों की दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा (टेली-मेडिसन)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह → दुर्लभ रोगों संबंधी एक व्यापक रणनीति की जरूरत है।
SDG-3 के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली व वन हेल्थ एप्रोच में दुर्लभ रोगों पर ध्यान देना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए, इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करने और उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

For realistic and effective collaborations to take place in the Indo-Pacific region, there is a need to acknowledge and recognize the underlining intention of the various countries with stakes in the region. Discuss. (Answer in 250 words) 15

एशिया-प्रशांत की जगह हिन्द-प्रशांत अवधारणा एक हिन्द महा. और प्रशांत महा० के देशों के मध्य एकीकृत भू-राजनीति व्यवस्था है। भारत इस व्यवस्था में केन्द्रीय भूमिका निभाता है।

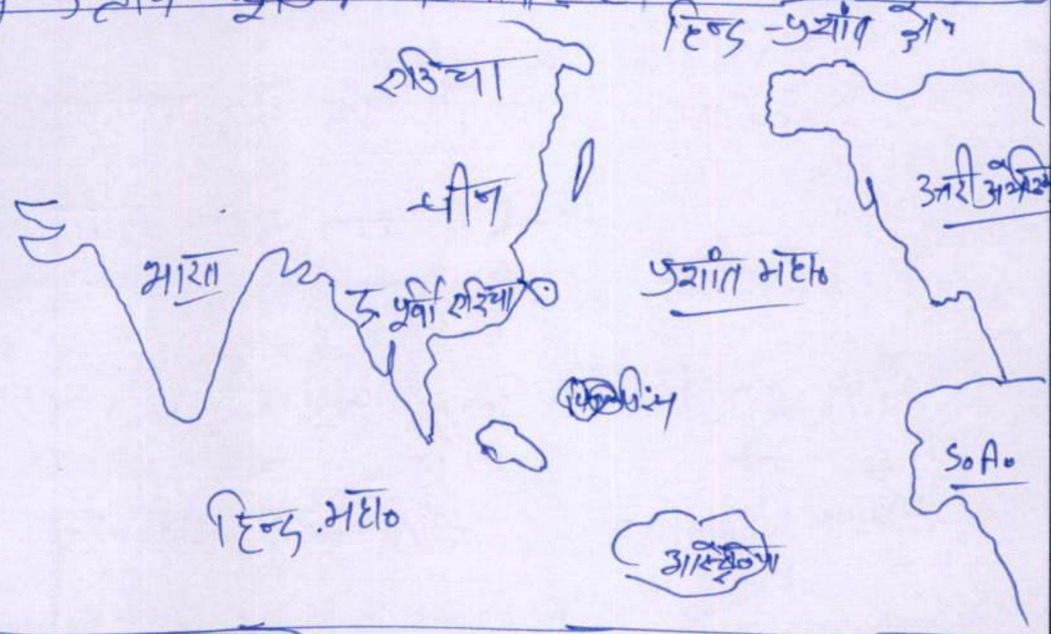

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का महत्व – विश्व की 65% आबादी है।
→ वैश्विक GDP का 62% और वैश्विक व्यापार का 50% इस क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में भारत, USA, चीन व रूस जैसे बड़े देशों के सामरिक हित जुड़े हैं।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए देशों के हितों की पहचान आवश्यक है-
① चीन की बढ़ती आक्रमकता को रोकने के लिए।
eg- दक्षिण चीन सागर विवाद
② क्वाड और AUKUS के कारण नए गठबंधनों का उभार हुआ।
③ भारत के लिए एक खुले, मुक्त, समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का महत्व
④ दक्षिण-पूर्वी (आसियान) देशों के लिए भू-राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक हित व महाशक्तियों के दबाव को बचाना।
⑤ USA के लिए IPEF की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
⑥ आस्ट्रेलिया के लिए चीन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को प्रतिसंतुलित करना जरूरी

(3) जापान व द० कोरिया के लिए 'चाइना प्लस' रणनीति के लिए जरूरी

(4) भारत नौवहन स्वतंत्रता व नियम आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का पक्षधर है।

भारत की पहल → "क्वाड" में शामिल होना

↳ फ्रांस-भारत-आस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह बनाना

↳ IPEF में 14 भागीदारों के साथ शामिल

(सागर विजन, IORA, IONS आदि) के साथ भागीदारी करना।

भारत समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर रहा है। अतः उसे अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थल के रूप में स्थापित होने से पहले, भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

There is a need to address the underlying challenges, both internal and external, in the North-Eastern region of India before it can serve as a pivotal connecting space between India and its neighbours. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 5 देशों के साथ 5000Km से अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है अतः इसका रणनीतिक महत्व है।

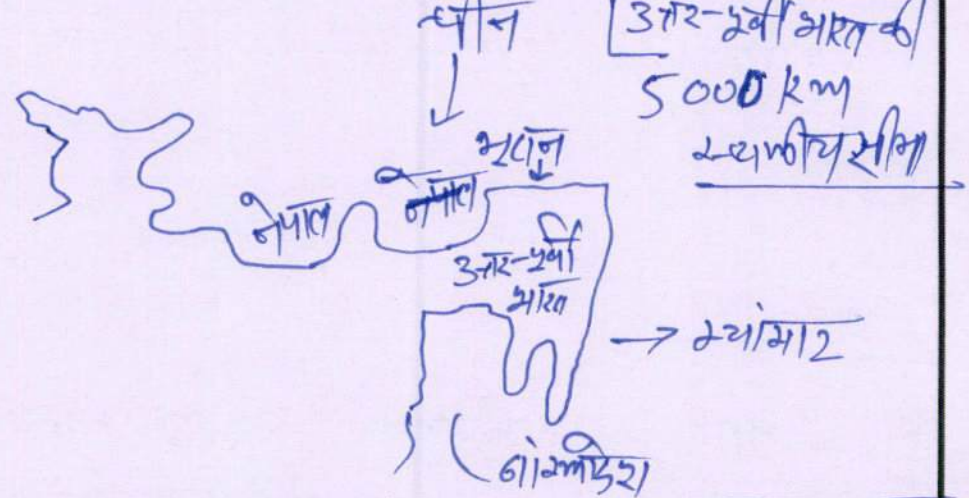

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक चुनौतियां

→ शरणार्थी समस्या के कारण सामाजिक संरचना पर प्रभाव
eg- म्यांमार व बांग्लादेश से शरणार्थी रोहिंग्या संकट

→ उत्तर-पूर्व का आर्थिक पिछड़ापन व कनेक्टिविटी का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ जनजातीय विविधता के कारण मुख्य संपर्क न हो पाना।

↳ उग्रवाद, नस्लवाद व राज्यों में भूमि विवाद का होना।
eg- मणिपुर हिंसा

बाह्य चुनौतियाँ → छिद्रिल सीमा का होना

↳ नारको तस्करी, मवेशी तस्करी उद्योग के कारण संगठित अपराध का बढ़ना।
eg- गोल्डन ट्राइंगल

↳ चीन द्वारा प्रायोजित माओवाद
eg उल्फा को शरण देना।

↳ सीमा प्रबंधन की चुनौती
eg- दुर्गम भूगोल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इंडिया → एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित
→ तकनीक द्वारा सीमा प्रबंधन
→ देशों के साथ समझौते
 ex- बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता

- सीमा बलों का आधुनिकीकरण
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी द्वारा रणनीतिक ध्यान देना
- कनेक्टिविटी बनाना
 ex- भारत त्रिपक्षीय राजमार्ग
 कलादान मल्टी मॉडल प्रो.
 अखौरा - अगरतला रेललिंक

अतः उत्तर पूर्व की सुरक्षा व विकास के लिए पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध।